बांड पॉलिसी को लेकर अनिल विज और मनोहर लाल आमने सामने

चण्डीगढ़ (म.मो.) 45 साल पहले मंत्री सुषमा स्वराज और चीफ मिनिस्टर देवीलाल भी आमने सामने हुए थे। क्या इतिहास दोहराया जा रहा है ? तब देवीलाल ने फरीदाबाद में एक सार्वजनिक समारोह में सुषमा स्वराज को अयोग्य बता मंत्री पद से बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया था। फरीदाबाद में मजदूरों पर गोली चलाने के विरोध में लेबर मिनिस्टर सुषमा स्वराज आग बबूला हो गयी थी और आंदोलन में शामिल मजदूरों से मिलने चली गयी थी। तब चन्द्रशेखर के दवाब में देवीलाल को अपना फैसला वापिस लेना पड़ा था।

राजनीतिक हलकों में यह सवाल पूछा जा रहा है कि मनोहर लाल क्या स्टैंड लेंगे क्योंकि विज द्वारा खुलकर डॉक्टरों के समर्थन में आने से हीरो बन गए है और मनोहर की छवि विलेन जैसी बन गयी है ?

हालांकि मुख्यमंत्री अपने महकमे के मंत्री की बात मानने के लिए बाध्य नहीं हैं लेकिन विज द्वारा स्टैंड लेने से मनोहर लाल की स्थिति हास्यपद हो गयी है।

हरियाणा में जरूरत है एक न्याय युद्ध की

फ़रीदाबाद (म.मो.)। देवीलाल जिसने न्याय युद्ध आंदोलन चला कर तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल की बंसी बजा दी थी। यह अलग बात है कि बाद में वो भी पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। लेकिन एक बार तो बंसी लाल को नाकों चने चबवा दिए थे। नागपुर, शाह और मोदी के आशीर्वाद से मनोहर लाल निरंकुश शासक हो गए है। लगता है कि अब भगवान कृष्ण भी अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे क्योंकि शायद अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह से वे भी सम्मोहित हैं। मान बड़ाई नानका तजना बहुत कठिन। आखिर अपनी प्रशंसा भगवान कृष्ण को भी तो अच्छी लगती होगी।

पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है। प्रॉपर्टी आई डी, तहसील में रजिस्ट्री, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी लेना हो आसानी से नहीं मिलता। कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। चंद अफसर इस तरह लूट रहे है की मोहम्मद गजनी को भी शर्म आये। सरकारी प्रॉपर्टी अपने चेलो को दी जा रही है। कुरुक्षेत्र में 10 एकड़ शहर के बीचों बीच में अपने ही बिरादरी के एक जो मनीषी कहलाता है। गुड़गांव में दूसरे भिरा पटौदी को.. अब ताज़ा तरीन सिंघल यूनिवर्सिटी के नाम रातों रात गोल माल ??

खनन माफिया, रेत माफिया और दादरी में दाड़म में माफिया। मीडिया पेड न्यूज़ में फंसा है। विपक्ष की कोई सुनता नहीं । सिर्फ बयानबाजी। क्योंकि इस हमाम में सब नंगे है।

रजिस्ट्रयों पर प्रतिबंध लगाने व हटाने का धंधा

फ़रीदाबाद (म.मो.) छोटे प्लॉटों के टुकड़ों केंपंजीकरण का कार्य बड़खल तहसील में काफी लंबे समय से बंद कर रखा था। जिससे व्यापारी डीलर एवं बिल्डर काफी परेशान थे। उनकी परेशानी को लेकर फीवा कार्यकारिणी का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से उनके कैंप कार्यालय में मिला और समस्या से अवगत कराया, उन्होंने मौके पर ही उपायुक्त एवं तहसीलदार को इन पाबंदियों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए। उसके बाद अब सामान्य तरीके से सब लोगों की रजिस्ट्रियां हो पा रही हैं। इसलिए सैनिक कॉलोनी एवं एनआईटी जोन के डीलर-बिल्डरों ने 6 दिसंबर दिन मंगलवार को शाम ठीक 6.00 बजे सैनिक कॉलोनी सेक्टर-49 की मार्केट में मंत्री जी के स्वागत एवं रात्रि भोज के कार्यक्रम का आयोजन किया।

फीवा ने अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी जनता को आमन्त्रित किया है। उक्त समस्या का समाधान करके मंत्री ने मानो जनता पर बहुत बड़ा अहसान कर दिया हो। इसके बदले व इनके वोटों के 'हकदार' तो हो ही गये। भोली-भाली जनता को शायद यह मालूम नहीं कि प्लॉटों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध भी मंत्री जी ने ही लगवाया था जोकि पूर्ण रूप से गैरकानूनी था। अब उसी प्रतिबंध को हटवाकर जनता की वाहवाही लूट रहे हैं। इसी को तो आज राजनीति कहते हैं।

पार्कों को बेचने का निर्णय शर्मनाक, सरकार क्या पूरी तरह कंगाल हो चुकी है

करनाल, कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने कहा कि मुख्यमन्त्री की नगरी करनाल मे पार्को को बेचने का सरकारी निर्णय शर्मनाक है। सरकार इतनी कंगाल हो चुकी है कि अब पार्को को बेचने की नौबत आ चुकी है।

शहर के पार्क सार्वजनिक संपत्ति एवं धरोहर हैं। लोगों की धरोहर हैं। यह किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है। सरकार एक तरफ फिजूलखर्ची कर रही है। दृष्टिहीन लोगों के लिए जो फुटपाथ करोड़ों की लागत से बना है, इसका कोई उपयोग नहीं है। प्रशासन ने लाखों खर्च कर राहधारी बनाई

त्रिलोचन सिंह

वह खराब पड़ी है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी राज मे अफसर और नेता दोनों हाथो से देश को लूट रहे हैं। करनाल नगरी मे भ्रष्टाचार चरम पर है। बीजेपी राज अंधो और भ्रष्ट लोगों के हाथों मे है।

इनका अगर जोर चले तो यह लोग कफन और शमशान भी बेच देंगे। मुख्यमन्त्री मनोहर लाल और उनके नेताओं का जमीर मर चुका है। बीजेपी अब लूट के चरम पर है। यहाँ सरकार अली बाबा चालीस चोर की कहावात चरितार्थ कर रही है।

आईडी बनाने वाली निकृष्ट कंपनी को मोटे भुगतान की तैयारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) डिजिटल इंडिया के सुनहरे ख्वाब दिखाते हुए खट्टर सरकार ने शहर की तमाम जायदादों की आईडी बनाने का ठेका याशी नामक एक कंपनी को करीब दो वर्ष पूर्व दिया था। जबतक किसी जायदाद की आईडी न बन जाय तब तक उसकी खरीद-फरोख्त की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती। और तो और नगर निगम में उसका हाउस-टैक्स नहीं भरा जा सकता। न ही 'हूडा' में उस जायदाद के लिये किसी प्रकार की कार्यवाही के लिये आवेदन किया जा सकता है।

पिछले दिनों इस निकृष्ट कंपनी द्वारा जो आईडी बना कर लोगों को भेजी गई थी, उनमें से शायद ही कोई ठीक पाई गई हो। अधिकांश में मालिकान के नाम व पते से लेकर प्लॉट एवं बिल्डिंग के साइज के बारे में तमाम उल्टी-सीधी जानकारियां दी गई हैं। इन्हें ठीक कराने के लिये एमसीएफ तथा 'हूडा' कार्यालय में लोगों का तांता लगा हुआ है। ठीक कराने के नाम पर बाबू लोग जनता को अच्छा-खासा परेशान करके लूटने में जुटे हैं।

याशी कंपनी द्वारा किये गये इस उल्टे-सीधे काम के बदले उसे अब मोटे भुगतान किये जाने की तैयारी है। यद्यपि इस भुगतान की सही रकम का तो पता नहीं चल पाया लेकिन इसे करोड़ों में बताया जा रहा है। इसके लिये इसे एमसीएफ की ओर से एनओसी दिये जाने के लिये बीते सोमवार को नगर निगम में कुछ चुनिंदा सरकार समर्थक समाज सेवियों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें हुए निर्णय की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है।

मिलावटी दुग्ध पदार्थों के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका

वरुण श्योकंद

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिल्ली - एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में मिलावटी व नकली दुग्ध उत्पादों की धड़ल्ले से सप्लाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, डीजी हेल्थ सर्विसेस, स्वास्थ्य सचिव व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

फरीदाबाद निवासी वरुण श्योकंद ने एडवोकेट आरएस चहल के माध्यम से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी पलवल, मेवात व नूंह में हर रोज 40 हजार किलो नकली व मिलावटी दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों को फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली व अन्य स्थानों पर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है।

इन दुग्ध उत्पादों को तैयार करने के लिए मैलामाइन, palmolein रिफाईण्ड ऑयल, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लिसरीन, यूरिया, स्टार्च व कास्टिक सोडा केमिकल का इस्तेमाल होता है।